भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3980

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

कोयला खदानों की प्रचालन दक्षता

3980. श्री दिनेशभाई मकवाणा:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्रीमती कमलेश जांगड़े:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष विगत एक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान विशेषकर छत्तीसगढ़ में दर्ज किए गए कोयले के अधिकतम उत्पादन और प्रेषण सहित घरेलू कोयले के उत्पादन की वृद्धि करने में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा कोयला खदानों की प्रचालन दक्षता को बढ़ाने, कोयला निष्कर्षण अवसंरचना को मजबूत करने तथा विशेषकर छत्तीसगढ़ में विद्युत क्षेत्र और अन्य प्रमुख उद्योगों को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क): वर्ष 2025-26 और चालू वर्ष (जून, 2026 तक) के दौरान देश और छत्तीसगढ़ राज्य में घरेलू कोयला उत्पादन और प्रेषण निम्नानुसार है:

[आंकड़े मिलियन टन (एमटी) में]

वर्ष	देश		छत्तीसगढ़ राज्य	
	उत्पादन	प्रेषण	उत्पादन	प्रेषण
2025-26 (अनंतिम)	1040.08	1018.29	222.04	223.33
2026-27 [जून, 2026 तक] (अनंतिम)	232.49	268.04	52.61	58.47

(ख): कोयला लॉजिस्टिक्स श्रृंखला में मुद्दों का समाधान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के समन्वय से कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक एकीकृत कोयला संभार तंत्र योजना के माध्यम से देश में कोयला निकासी की अवसंरचना को कोयला उत्पादन में अनुमानित वृद्धि के अनुरूप बढ़ाया जा रहा है। कोयला संभार तंत्र योजना में 33 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं के विकास, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) अवसंरचना का विस्तार, रेल मंत्रालय के परामर्श से रेल निकासी क्षमता में वृद्धि और रेल, तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करने के लिए, वित्त वर्ष 2029-30 तक 1319 मि.ट. क्षमता वाली 139 एफएमसी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा, कोयला पीएसयू कोयला धारक राज्यों में कोयला निकासी को आसान बनाने और देश में विद्युत क्षेत्र और अन्य प्रमुख उद्योगों को समय पर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं को भी लागू कर रहे हैं।

इन पहलों से मशीनीकृत कोयला हैंडलिंग में वृद्धि होगी, लदान समय में कमी आएगी, निकासी दक्षता में सुधार होगा और छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश के सभी उपभोक्ता क्षेत्रों को समय पर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

*****